hasty decision. But we do not want to take away private doctors from the provisions of the Consumer Protection Act.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : You were hasty about private doctors, why are you not hasty about Government doctors ?

उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हेतु उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र

*243. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु हाल ही में उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु क्या-क्या विशेष प्रावधान किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है, और यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) इस समझौते के तहत किन-किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ); जी हां। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कंज्यूमर एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर (सी ई आर सी) अहमदाबाद को आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक परियोजना आरम्भ करने हेतु एक करार किया है, ताकि, यह सेंटर उत्पादों के तीन महत्वपूर्ण वर्गों, अर्थात् खाद्य, औषधियों तथा बिजली के घरेलू उपकरणों के तहत आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का तुलनात्मक परीक्षण, श्रेणीकरण तथा मूल्यांकन कर सकें। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया के तहत, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को कार्यकारी एजेंसी तथा सी.ई.आर.सी. को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है। मंत्रालय ने सी आर सी के साथ एक करार किया है, जिसके तहत उक्त केंद्र ने लागू नियमों तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक कार्य विभाग के निर्देशों के अनुसार सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना स्वीकारा किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा तथा उत्पादों की गुणवत्ता की दृष्टि से उपभोक्ताओं को जानकारी के साथ विकल्पों में से किसी का चुनाव करने में सहायता प्रदान करना है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करके उत्पादकों/विनिर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों के बारे में किए गए दावों की भी जांच करेगा। कंज्यूमर एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर ऐसे उत्पादों के संबंध में प्राप्त अपने परिणामों से संबंधित सूचना का व्यापक रूप से प्रसार करने की भी व्यवस्था करेगा। इससे उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने तथा साथ ही यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि उपभोक्ता गुणवत्ता वाले उत्पादों को खरीदें तथा उत्पादकों/विनिर्माताओं द्वारा भ्रमित न किए जा सकें।

इस परियोजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण करने के लिए तीन समितियां, अर्थात् परियोजना सलाहकार समिति, परियोजना संचालन समिति तथा त्रय समिति गठित की गई हैं। नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कार्यकारी एजेंसी के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरत रहा है कि परियोजना को कार्यान्वित करने के मामले में नियम व विनियम तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आर्थिक कार्य विभाग आदि के अनुदेशों का सी ई आर सी द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाए।

श्री दिलीप सिंह जूदेव : उपसभापति महोदया, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आदिवासी और पिछड़े इलाके के जो लोग हैं उनको इसका

पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस इलाके में शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे होने के कारण लोगों में गुणवत्ता और वस्तु की कीमत का सभी ज्ञान नहीं हो पाता। इसके परिणामस्वरूप यहां के लोगों को दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा लूटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में खास करके आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना और इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सरकार क्या विशेष कार्य का योजना बनाकर कदम उठाने वाली है?

श्री कमालुद्दीन अहमद : इसमें जो सवाल किया गया है वह कंज्यूमर एजूकेशन रिसर्च सेंटर का है और यू.एन.डी. पी. के साथ जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके ताल्लुक से सवाल है। यह प्रोजेक्ट शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। बिल्डिंग वगैरा तैयार हो रहा है।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI : Will it cover Madhya Pradesh tribals ? That is what the hon. Member wants.

SHRI KAMLUDDIN AHMED : It covers.

यह इंस्टीट्यूशन पूरा का पूरा देश के लिए कारआमद होगा। कंपेरेटिव टेस्टिंग के लिए आ रहा है यह आर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसका लाभ सारे देश को होगा और खास तौर से इसमें जो आहार पदार्थ है जो गिजा के आइटम्स हैं मेडिसिन्स हैं और पब्लिक के स्वास्थ्य से जिनका संबंध है, पब्लिक की सिक्योरिटी से जिनका संबंध है, जैसे इलेक्ट्रिक एप्लायेंसेज वगैरह है इनकी कंपेरेटिव टेस्टिंग होगी। इनके ताल्लुक से सारी जानकारी देश को मिलेगी और उसके लिहाज से काम किया जाएगा।

उपसभापति : ट्रेनिंग भी देंगे ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : ट्रेनिंग से मतलब एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, सिर्फ कंपेरेटिव टेस्टिंग होगी और उससे जो लोगों को एजुकेशन होगी, जानकारी होगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों से उपभोक्ता और गुणवत्ता के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए जिलास्तर पर केन्द्रीय समिति का गठन करने हेतु क्या कोई योजना विचाराधीन है जिससे आदिवासी लोगों को उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : इसकी इन्फारमेशन लेकर मैं पास आन कर दूंगा इसलिए कि इस सवाल से उसका कोई संबंध नहीं है।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI : What does your agreement contemplate ? Will there be monitoring at the district level or not ? And what are you doing to spread awareness ?

SHRI KAMLUDDIN AHMED : This question relates to the CERC and the UNDP Project. I said that I would collect the information on how many complaints have been received in the State of Madhya Pradesh, what action has been taken and how many district forum judgements have come and would pass it on to the hon. Member. I can pas on all those details. There is no problem about it.

श्री चतुरानन मिश्र : महोदया पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को इस ट्रेनिंग में रखेंगे कि नहीं

It is the Finance Ministry which is not listening to to this. So, are you going to train the Finance Minister or not ? This is my first question. First train your Finance Minister. Are you going to train him or not ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, no, that does not arise.

SHRI CHATURANAN MISHRA : Because he does not listen to it.

THE DEPUTY CHAIRMAN : That question does not arise out of this.

आप अपना सवाल पूछ लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : इसी से रिलेटेड है चूंकि मेरी रिक्वेस्ट को

The Finance Ministry so far has not listened to your Ministry though it is a very noble job that you have done. This is the first time that it is being done. Are you going to represent this to the Prime Minister or not ? So, please reply to these two points. First train the Finance Minister. Then tell the Prime Minister that this has not been translated.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A.K. ANTONY): The Finance Minister has given a reply to our Ministry that the Finance Ministry is seriously examining the BICP report and that it would take action. So, there is no question of going to the Prime Minister. The Government is one. We are taking decisions collectively. So, the Finance Ministry is seriously following that BICP report. It will take action.

SHRI CHATURANAN MISHRA : The second part is if you are going to the Prime Minister for this. You have given a very pathetic reply that nobody is listening and that you have requested the administrative departments or the Finance Ministry. Nobody is listening. The whole year is ending. Are you going to pay the consumers for their redressal. It is a continuing process after the Budget relief. So, are you going to the Prime Minister or not ? That is my simple question.

SHRI KAMALUDDIN AHMED : That question is over. It was Q. No. 242. You are asking about Q. No. 242.

SHRI CHATURANAN MISHRA : I am asking about the training of the Finance Minister. That is for the Chair to decide.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Whether he will go to the Prime Minister or not, that cannot be a question. If the Finance Minister needs any training he will ask for it.

SHRI CHATURANAN MISHRA : My question is whether he will go to the Prime Minister or not.

SHRI KAMALUDDIN AHMED : The Finance Minister has already given a reply that they are seriously examining the BAC Report and after that they will take action.

SHRI CHATURANAN MISHRA : When will they take action ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shrimati Kamla Sinha.

SHRIMATI KAMLA SINHA : I am glad that the Minister has come out with a reply that they are going to train consumers through the UNDP help. With only one unit in Ahmedabad, I do not think it will serve the purpose. So, to accelerate the process of awareness it is necessary that at least one such institute should be started in each State. I would like to know whether the Government is going to do that and in that process whether women will be given greater consideration because it is they who are the basic consumers in the House.

SHRI KAMALUDDIN AHMED : There are a number of organisation which are voluntary organisations. There is no Government organisation as such and there is no proposal as such to have a specific training centre for women or for any particular State. A number of voluntary organisations have set up such centres. The CERC is also one such organisation. It is a voluntary organisation.

*244.[*The Questioner (Shri Ish Dutt Yadav) was absent. For Answer vide col.....infra.*]

*245. [*The Questioner (Shri Krishan Lal Sharma) was absent. For Answer vide col.....infra.*]

*246. [*The Questioner (Shri J. P. Jawali) was absent. For Answer vide col.....infra.*]

THE DEPUTY CHAIRMAN : Q. No. 247 is transferred.